दृष्टि The Vision

drishti

GENERAL STUDIES (Test–3)

निर्धारित समय: तीन घंटे
Time allowed: Three Hours

DTVF/22 (J-A)–M–**GSM (M-I)-2203**

अधिकतम अंक: 250
Maximum Marks: 250

Name: Rajnish Patel

Mobile Number:

Medium (English/Hindi):

Reg. Number:

Center & Date:

UPSC Roll No. *(If allotted)*:

प्रश्न-पत्र के लिये विशिष्ट अनुदेश

कृपया प्रश्नों का उत्तर देने से पूर्व निम्नलिखित प्रत्येक अनुदेश को ध्यानपूर्वक पढ़ें:
इसमें बीस प्रश्न हैं तथा हिन्दी और अंग्रेज़ी दोनों में छपे हैं।
सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने दिये गए हैं।
प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम में लिखे जाने चाहियें जिसका उल्लेख आपके प्रवेश-पत्र में किया गया है, और इस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न-सह-उत्तर (क्यू.सी.ए.) पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर अंकित निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिये। उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिखे गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।
प्रश्नों में शब्द सीमा, जहाँ विनिर्दिष्ट है, का अनुसरण किया जाना चाहिये।
प्रश्न-सह-उत्तर-पुस्तिका में खाली छोड़ा हुआ पृष्ठ या उसके अंश को स्पष्ट रूप से काटा जाना चाहिये।

QUESTION PAPER SPECIFIC INSTRUCTIONS

Please read each of the following instruction carefully before attempting questions:
*There are **TWENTY** questions printed both in **HINDI** and **ENGLISH**.*
All the questions are compulsory.
The number of marks carried by a question is indicated against it.
Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate which must be stated clearly on the cover of this Question-cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in a medium other than the authorized one.
Word limit in questions, wherever specified, should be adhered to.
Any page or portion of the page left blank in the Question-cum-Answer Booklet must be clearly struck off.

केवल मूल्यांकनकर्त्ता द्वारा भरा जाए *(To be filled by Evaluator only)*

Question Number	Marks	Question Number	Marks
1.		11.	
2.		12.	
3.		13.	
4.		14.	
5.		15.	
6.		16.	
7.		17.	
8.		18.	
9.		19.	
10.		20.	
Grand Total (सकल योग)			

S Kumar
मूल्यांकनकर्त्ता (हस्ताक्षर)
Evaluator (Signature)

पुनरीक्षणकर्त्ता (हस्ताक्षर)
Reviewer (Signature)

drishti | दृष्टि The Vision

Feedback

1. Context Proficiency (संदर्भ दक्षता)
2. Introduction Proficiency (परिचय दक्षता)
3. Content Proficiency (विषय-वस्तु दक्षता)
4. Language/Flow (भाषा/प्रवाह)
5. Conclusion Proficiency (निष्कर्ष दक्षता)
6. Presentation Proficiency (प्रस्तुति दक्षता)

---

1) प्रश्न संख्या – 9, 10, 11 तथा 14 में सुझाए गए ढाँचे से संदर्भ को दक्ष बनाया जा सकता है

2) प्रश्न संख्या – 1, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19 तथा 20 में सुझाए गए बिन्दुओं से भूमिका को प्रभावी बनाया जा सकता है

3) प्रश्न संख्या – 1, 5, 6, 8, 13, 15, 17 तथा 19 में सुझाए गए बिन्दुओं से विषय वस्तु को दक्ष बनाया जा सकता है

4) भाषा एवं प्रवाह ठीक है

5) प्रश्न संख्या – 7, 8, 15, 18 तथा 19 में सुझाए गए बिन्दुओं से निष्कर्ष को प्रभावी बनाया जा सकता है

6) प्रस्तुती के स्तर पर रेखांकन (underline) को बढ़ा सकते हैं। विश्लेषण वाले प्रश्नों में चैट फॉर्म का प्रयोग कर सकते हैं

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

1. विद्युत क्षेत्र की प्रमुख संरचनात्मक चुनौतियों पर प्रकाश डालिये। इन चुनौतियों के समाधान के कुछ उपाय सुझाइये। (150 शब्द) 10
Highlight the major structural challenges ailing the power sector. Suggest some measures to overcome these challenges. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

भारत द्वारा विद्युत उत्पादन अधिशेष होने के बावजूद आवश्यकतानुरूप सभी क्षेत्रों को 24 घंटे विद्युत आपूर्ति न हो पाना संरचनात्मक कमियों की तरफ इंगित करता है।

(Evaluator's margin note: आँकड़े साथ में देते तो विषयवस्तु प्रभावी बनती है)

विद्युत क्षेत्र की प्रमुख संरचनात्मक चुनौतियाँ

(Evaluator's margin note: संदर्भ एवं प्रस्तुती अच्छी है)

⇒ विद्युत वितरण कंपनियाँ घाटे में चल रही हैं, साथ ही कई कर्ज के चलते डिफाल्ट होने की स्थिति में हैं।

⇒ विद्युत क्षेत्र में उपभोक्ताओं द्वारा समय से बिल भुगतान न करना, बिजली चोरी जैसी समस्याएँ भी व्याप्त हैं।

⇒ कृषि आदि क्षेत्रों के साथ-साथ लगातार विद्युत सब्सिडी का विस्तार एक समस्या है

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

⇒ पारेषण क्षमता एवं तकनीक परम्परागत होने से विद्युत क्षय अधिक है।

⇒ नवीकरणीय विद्युत खरीद दायित्वों ने लागत में वृद्धि की है।

चुनौतियों के समाधान हेतु उपाय

⇒ UDAY 2.0 योजना का संचालन किया जा रहा है।

⇒ साथ ही केंद्रीय विद्युत नियामकों एवं राज्य नियामकों को विकेन्द्रित नवीकरणीय क्षमता (सोलर पैनल आदि) पर विकास की जरूरत है।

⇒ इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ाए जाने की जरूरत है।

वस्तुत: नवीकरणीयता के दृष्टिकोण के साथ-साथ वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड जैसी योजनाएँ सच्चालनात्मक परिवर्तनता रखती हैं।

Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

2. "भारत में आजादी मिलने के बाद से खंडित भूमि जोत एक मुख्य समस्या बनी हुई है।" कृषि क्षेत्र पर इसके प्रभाव का परीक्षण कीजिये। (150 शब्द) 10

"Fragmented landholding has been an issue since India gained independence." Examine its impact on the agriculture sector. (150 words) 10

भारत के 80% से अधिक कृषक छोटे एवं सीमांत श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं जो भारतीय कृषि के पिछड़ेपन का प्रमुख कारण है। इन छोटे एवं सीमांत किसानों के पास भी जो भूमि है वह खंडित ही है जो समस्या को तीव्र करती है।

खंडित भूमि जोत के कारण

⇒ चकबंदी जैसी प्रक्रियाओं का सुचारु रूप से क्रियान्वयन न होना।

⇒ पारिवारिक विभाजन से लगातार जोत का विभाजित होते रहना।

⇒ जनसंख्या वृद्धि

⇒ सामूहिक कृषि प्रथा का विकास न होना।

Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

कृषि क्षेत्र पर खंडित भूमि संरचना का प्रभाव

→ किसानों की लागत में वृद्धि होती है उन्हें हर खेत में पानी के लिए अलग से व्यवस्था करनी होगी।

→ कृषि में मशीनीकरण की संभावनाएँ सीमित होती हैं क्योंकि बड़ी मशीनों का संचालन संभव नहीं होता है।

→ उत्पादकता भी प्रभावित होती है क्योंकि किसान के लिए सभी पर बराबर ध्यान देना संभव नहीं होता है

→ कृषि में निवेश भी प्रभावित होता है एक जगह जमीन होने से किसान पर्याप्त अवसंरचनात्मक निवेश हेतु प्रोत्साहित होता है।

वस्तुत: कॉरपोरेट कृषि जैसी प्रणालियाँ इस दिशा में क्रांतिकारी बदलाव ला सकती हैं इसी तरह कृषि उत्पादक कंपनियों की स्थापना भी एक सहायक कदम हो सकता है।

छद्म/प्रच्छन्न बेरोजगारी में वृद्धि
> संस्थागत ऋण प्राप्त करने में कठिनाई
> भूमि संसाधन का प्रभावी उपयोग में बाधा (हजारों हेक्टेयर मेड़)
5
अच्छा प्रयास है
→ ठीक है

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

3. वैश्विक आपूर्ति एकीकरण में भारत में एम.एस.एम.ई. के समक्ष आने वाली विभिन्न चुनौतियाँ क्या हैं? इन समस्याओं के समाधान में सरकारी हस्तक्षेप कैसे उपयोगी रहे हैं? (150 शब्द) 10

What are the various challenges faced by MSME's in India in global supply integration. How have government interventions been useful in addressing the issues? (150 words) 10

भारत के सकल निर्यात में MSME द्वारा लगभग 40% का योगदान दिया जाता है फिर भी अभी तक यह वैश्विक मूल्य श्रृंखला का हिस्सा नहीं बन सका है, जिसके अधोलिखित कारक नजर आते हैं।

1) भारत RCEP, EU जैसे किसी बड़े मुक्त व्यापार समूह का हिस्सा नहीं है

2) भारतीय MSME क्षेत्रक का तकनीकी कौशलात्मक विकास पिछड़ा हुआ है अत: वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा करने में यह अक्षम है।

3) बड़ी कंपनियाँ MSME से वस्तुओं की आपूर्ति प्राप्त करने में हिचकिचाती हैं क्योंकि ज्यादातर MSME अनौपचारिक क्षेत्रक में आते हैं अत: GST रिटर्न प्राप्त करने में कंपनियों को

→ ठीक है
संदर्भ क्षमता अच्छी है
→ मंहगे ऋण
→ बाजार तक पहुँच का अभाव
→ अपर्याप्त अवसंरचना
→ महामारी के बाद की चुनौतियाँ

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

दिक्कत आती है।

4) भारतीय लघु एवं मध्यम विनिर्माण क्षेत्रक इकॉनॉमी ऑफ स्केल की अवधारणा को चरितार्थ करने में अक्षम रहा है।

महत्वपूर्ण बिन्दुओं को रेखांकित करने का प्रयास करें

MSME क्षेत्रक हेतु प्रयास (सरकारी)

- → मुद्रा योजना द्वारा वित्तीय सहायता।
- → ई-ट्रेड रिसीवेबल की अवधारणा।
- → रोडटेप जैसी योजना द्वारा निर्यात प्रोत्साहन। → PLI योजना द्वारा प्रोत्साहन
- → मेक इन इंडिया जैसी योजना द्वारा MSME क्षेत्रक एवं बड़ी कंपनियों को साथ लाने का प्रयास हुआ है।

→ प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम

→ पेटेंट संबंधी जागरूकता (कपिला अभियान)

प्रभाव
- → खासतौर से रक्षा विनिर्माण क्षेत्रक में MSME की सहभागिता बढ़ी है
- → MSME द्वारा PLI योजना का विशेष लाभ वस्त्र निर्यात क्षेत्रक में देखा जा रहा है। → ठीक है
- → इलेक्ट्रानिक विनिर्माण में भारतीय हिस्सेदारी बढ़ी है

4.5

अच्छा प्रयास है

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

4. भारत में कुपोषण को दूर करने में फूड फोर्टिफिकेशन महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। विवेचना कीजिये। (150 शब्द) 10

Food fortification can play a crucial role in addressing malnutrition in India. Examine. (150 words) 10

फूड फोर्टिफिकेशन से आशय

खाद्य पदार्थों में आवश्यक पोषक तत्वों जैसे- विटामिन, आयरन आदि का मिश्रण करने से है। भारत जैसे बड़ी कुपोषित आबादी वाले देश के लिए इसे एक महत्वपूर्ण अवधारणा के रूप में देखा जा रहा है।

संदर्भ एवं प्रस्तुति अच्छी है

कुपोषण दूर करने में इसकी भूमिका
- पोषक तत्वों का खाद्य पदार्थों में मिश्रण संभव होगा।
- अन्य उपायों की तुलना में यह लागत प्रभावी है।
- खाद्य आदतों में परिवर्तन किए बिना ऐसा करना संभव है।
- स्वाद, रंग रूप आदि में कोई विशेष परिवर्तन नहीं करना पड़ता है।

→ बच्चों एवं महिलाओं स्वास्थ्य में सुधार

उदा- आटा में आयरन मिलाकर PDS के माध्यम से वितरित

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

सरकार द्वारा हाल में उठाए गए कदम

→ मिड-डे मील एवं खाद्य सुरक्षा योजना में इसे शुरुआती तौर पर लागू किया जा रहा है।

→ चावल खाने वाले क्षेत्रों में प्रोटीन की अल्पता दूर करने हेतु फोर्टिफिकेशन हो रहा है।

फूड-फोर्टिफिकेशन की सीमाएँ

→ यह प्राकृतिक व्यवस्था में कृत्रिम परिवर्तन है।

→ दूरगामी परिणामों के संदर्भ में आंकड़ों की कमी है।

वस्तुतः कुपोषण से लड़ने की दिशा में फोर्टिफिकेशन को एक कदम के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए न कि एकमात्र कदम के रूप में।

→ द इंडिया न्यूट्रिशन इनिशिएटिव

→ किसी विशेष सूक्ष्म पोषक तत्व तक सीमित न कि सभी सूक्ष्म पोषक तत्वों पर

→ अतिपोषणता संबंधी समस्या

→ छोटे मिल मालिकों द्वारा तकनीक का वहन न कर पाने की समस्या

→ ठीक है

5

अच्छा प्रयास है

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

5. आदेशात्मक नियोजन से आप क्या समझते हैं? यह निर्देशात्मक नियोजन से किस प्रकार भिन्न है? (150 शब्द) 10

What do you understand by Imperative Planning? How is it different from Indicative planning? (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

नियोजन से आशय उपलब्ध संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए तय समय में लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु योजना तैयार करने से है। इसके कई प्रकार होते हैं जिसमें से दो प्रमुख हैं-

→ 800

निदेशात्मक नियोजन ← → आदेशात्मक नियोजन

आदेशात्मक नियोजन के अन्तर्गत तय समय में निश्चित परिमाणात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु सभी कार्यरत संस्थाओं को आदेशित किया जाता है। उदाहरणार्थ:- समाजवादी अर्थव्यवस्थाओं में यह प्रणाली प्रायः प्रचलन में पायी जाती है।

संदर्भ स्पष्टता एवं प्रस्तुतीकरण अच्छी है

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

आदेशात्मक नियोजन	निर्देशात्मक नियोजन
⇒ मात्रात्मक रूप से तय लक्ष्य निर्धारित होते हैं।	⇒ इसमें केवल हर क्षेत्रक में एक विकास की दिशा निर्धारित की जाती है न कि मात्रा।
⇒ कठोरता से अनुपालन पर बल होता है।	⇒ कठोरता की जगह लोचशीलता होती है।
⇒ टॉप-डाउन दृष्टिकोण होता है।	⇒ बॉटम अप दृष्टिकोण होता है।
⇒ यहाँ स्पष्ट आदेश दिया जाता है।	⇒ संस्थाओं को कार्यात्मक माहौल उपलब्ध कराने का प्रयास होता है।

→ उद्देश्य → कल्याण बनाम लाभ
→ दिशा निर्देश → अलोकतांत्रिक बनाम लोकतांत्रिक
→ अप्रतिस्पर्धी बनाम प्रतिस्पर्धी
→ बाध्यकारी बनाम अबाध्यकारी

वस्तुत: वर्तमान संदर्भ में निर्देशात्मक नियोजन को अधिक उपयुक्त एवं सफल माना जाता है। भारत में नीति आयोग का दृष्टिकोण निर्देशात्मक ही है।

(5) अच्छा प्रयास है

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

6. भारत को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये कृषि क्षेत्र को सब्सिडी देने के बजाय कृषि में अनुसंधान एवं विकास के वित्तपोषण पर अधिक ध्यान देना चाहिये। चर्चा कीजिये। (150 शब्द) 10
India should be biased toward funding R&D in agriculture rather than giving subsidies to agriculture sector to ensure food security. Discuss. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

खाद्य सुरक्षा से आशय सभी व्यक्तियों की पर्याप्त खाद्य तक पहुँच सुनिश्चित करने से है। भारत में खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 इस दिशा में महत्वपूर्ण साधन है। हालांकि इसे सतत बनाए रखने हेतु अधोलिखित परिवर्तन अपेक्षित हैं। → ठीक है

खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में वर्तमान रणनीति ⇒ न्यूनतम समर्थन मूल्य जैसी प्रणाली द्वारा खाद्यान्न खरीद
↳ भंडारण ↳ वितरण सस्ते दामों पर।

वर्तमान प्रणाली में समस्या क्या है?
→ सरकारी राजस्व पर बोझ
→ भ्रष्टाचार
→ वर्तमान प्रणाली कृषि में नवीन प्रयासों में बाधक
→ पोषण सुरक्षा प्राप्त करने में यह अक्षम है

आँकड़े के प्रयोग से इस पक्ष को स्थापित किया जा सकता है। 2020 आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार सब्सिडी में व्यय किया गया प्रत्येक ₹1 का उत्पादकता ₹1 व कम था जबकि ... में ₹11.2 था ... और सबसे ... बॉक्स सब्सिडी की ...

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

क्या किया जाना चाहिए

→ सब्सिडी का स्थानांतरण R&D की तरफ करने से

→ गुणवत्तापूर्ण बीज निर्माण सम्भव होगा।

← कृषि का तकनीकी विकास होगा।

→ कृषि पर जलवायु परिवर्तन प्रभाव को सीमित किया जा सकेगा।

→ उत्पादकता में वृद्धि होगी।

→ फसल विविधीकरण पोषण सुरक्षा में सहायक होगा।

कृषि में आत्मनिर्भरता का विकास होगा।

→ लागत में कमी होने से वैश्विक बाज़ार में प्रतिस्पर्धा के अनुरूप

→ कृषि का मशीनीकरण सम्भव (महिलाओं के आवश्यकता के अनुरूप मशीन निर्माण)

वस्तुतः उपरोक्त प्रणाली WTO के नियमों के अधीन एक दूरदर्शी एवं सतत व्यवस्था का निर्माण करेगी। → ठीक है

4.5

अच्छा प्रयास है

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

7. जलवायु परिवर्तन और पानी की कमी के युग में, सूक्ष्म सिंचाई फसल की उपज बढ़ाने और पानी की आवश्यकताओं को कम करने में मदद कर सकती है। चर्चा कीजिये। (150 शब्द) 10

In the age of climate change and water scarcity, micro-irrigation can help increase crop yield and decrease water requirements. Discuss. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

यूनेस्को द्वारा विश्व जल विकास रिपोर्ट में भारत को सर्वाधिक जल संकट प्रभावित देशों में शामिल किया गया है। भारत अभी भी एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है अतः जल संकट का प्रभावी समाधान निकालना समय की मांग है। → ठीक है

good.

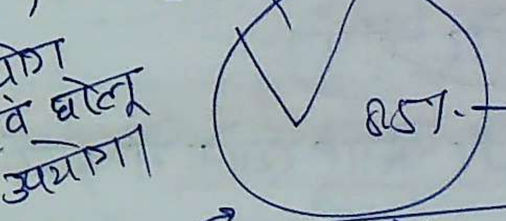

भारत में जल उपयोग

भारत में सूक्ष्म सिंचाई की आवश्यकता क्यों?

संदर्भ सूक्ष्मता एवं प्रस्तुतीकरण अच्छे है

→ यहाँ अभी भी जल दक्षता अत्यन्त निम्न है। एक किलो चावल उत्पादन में 3500 लीटर पानी का उपभोग होता है।

Copyright – Drishti The Vision Foundation

यहाँ पर किसानों को बिजली सब्सिडी दी जाती है जिससे जल गहन सिंचाई को प्रोत्साहन मिल रहा है।

⇒ भारत कृषि के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से जल का निर्यात करता है।

सूक्ष्म सिंचाई से लाभ

→ जल दक्षता में सुधार होगा (पर ड्रॉप मोर क्रॉप)

भूजल स्तर बनाए रखने में मदद मिलेगी।

→ सूक्ष्म सिंचाई पद्धति में अनावश्यक क्षेत्र में जल नहीं दिया जाता है जिससे खरपतवार की समस्या कम रहती है। उत्पादकता बढ़ती है।

वस्तुतः इस दिशा में राज्य एवं केंद्र सरकारों द्वारा सहायिकी उपलब्ध करायी जा रही है।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517

8. फसल विविधीकरण को टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने, आयात पर निर्भरता में कमी और किसानों के लिये उच्च आय को बढ़ावा देने के लिये एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। टिप्पणी कीजिये। (150 शब्द) 10

Crop diversification can be used as a tool to promote sustainable agriculture, reduction in import dependence and higher incomes for the farmers. Comment. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

फसल विविधीकरण से आशय एकल फसल उत्पादन के अलावा विभिन्न प्रकार की फसलों का उत्पादन करना है। इसके अधोलिखित लाभ हैं —

1) टिकाऊ कृषि → मृदा गुणवत्ता बनाए रखने में मदद मिलती है जैसे - खाद्यान्न के बाद दलहन कृषि से नाइट्रोजन गुणवत्ता में सुधार।

→ सभी फसलों हेतु बराबर मात्रा में जल की आवश्यकता नहीं होती अतः जल की खपत को भी सीमित किया जा सकता है।

2) आयात निर्भरता में कमी → विविध फसलों की उपलब्धता से बाह्य निर्भरता समाप्त होगी।

→ निर्यात की संभावना भी।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright - Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

किसानों की आय → फसल विविधीकरण कॉब वेब जैसे संकट से बचाता है जब सभी किसान एक ही प्रकार की कृषि करते हैं तो उस फसल का मूल्य ह्रास होता है।

→ जलवायु परिवर्तन का न्यूनतम प्रभाव

→ उत्पादकता में वृद्धि तथा लागत में कमी

फसलों का विविध उत्पादन निर्यात को प्रोत्साहित कर किसान की आय में सहायक होगा।

वस्तुतः इसके अतिरिक्त पोषण सुरक्षा जैसे लाभ भी प्राप्त होंगे।

5

फसल विविधीकरण को कैसे बढ़ावा दिया जाए, इसका समाधान देते हुए निष्कर्ष लिखा जा सकता है

9. दोहरे घाटे (Twin Deficit) की अवधारणा की व्याख्या कीजिये? भारत वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में दोहरे घाटे की चुनौती की फिर से उभरती चुनौती से कैसे निपट सकता है। (150 शब्द) 10

Explain the concept of twin deficit? How can India address the re-emerging challenge of twin deficit challenge in current global scenario. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

दोहरे घाटे से तात्पर्य कंपनियों द्वारा लिए गये कर्ज का NPA में परिवर्तन होना एवं इससे बैंकों की वित्तीय स्वास्थ्य का प्रभावित होना है। यह अवधारणा सर्वप्रथम अरविन्द सुब्रह्मण्यम ने प्रस्तुत किया।

यह Twin balance sheet problem है

राजकोषीय घाटा एवं CAD घाटा से संबंधित है

इस चुनौती से निपटने के उपाय :-

> भारत द्वारा इन्सॉल्वेंसी एवं बैंकरप्सी कोड का निर्माण किया गया है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय दिवालियापन जैसे प्रावधान शामिल करने की जरूरत

> बैंकों के समामेलन द्वारा उनकी सुभेद्यता को कम किया जा सकता है

संदर्भ में सुधार करें

Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

→ इसके अतिरिक्त सब प्राइम लेंडिंग द्वारा आर्थिक विकास को लक्षित करने की लालच से बचने की जरूरत है

→ NPA की समस्या के त्वरित निपटान हेतु इनसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एवं डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल आदि को मजबूत करने की आवश्यकता है

→ बॉन्ड मार्केट को मजबूत किया जाना चाहिए

10. महामारी और आसन्न मंदी के मद्देनजर, राज्यों को राजस्व की कमी के मुद्दे का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में राजकोषीय संघवाद के सिद्धांत को कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है? (150 शब्द) 10

In the wake of pandemic and looming recession, states are facing the issue of a revenue shortfall. In this regard how can the principle of fiscal federalism be ensured? (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

राजकोषीय संघवाद सुनिश्चित करने के उपाय

→ G.S.T. के अन्तर्गत प्रस्तावित प्रतिपूर्ति का समयपूर्वक आवंटन हो

→ राज्यों की कर्ज लेने की सीमा का विस्तार किया जाय

→ राजस्व प्राप्ति हेतु राज्यों को सक्षम बनाने हेतु कृषि आय पर कर आदि को प्रोत्साहित किया जा सकता है

→ प्रोफेशनल कर की संवैधानिक सीमा में वृद्धि की जा सकती है

→ अतिरिक्त अनुदान प्रदान किया जा सकता है

राजकोषीय संघवाद के संक्षिप्त परिचय से शुरुआत की जा सकती है

राजस्व हस्तांतरण में राज्यों के सामने आने वाले मुद्दों को संक्षेप में लिखें

→ 12% की भिन्न मध्यम एकल दर लगाकर

→ किसिन मुद्दे में राज्यों को अधिमान बनाने की मंजूरी दे देना

2

Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

drishti | दृष्टि The Vision

11. समावेशी विकास को बढ़ावा देने और सतत् विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये भारत में महिला श्रम बल की भागीदारी बढ़ाना महत्त्वपूर्ण है। इसे बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा कीजिये। (250 शब्द) 15
Increasing Female Labour Force Participation in India is crucial to promote inclusive growth and achieve the Sustainable Development Goals. Discuss the ways in which it can be increased. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

लैंगिक समानता से संबंधित SDG 4.0 हो या फिर भुखमरी, गरीबी आदि से संबंधित अन्य सतत विकास लक्ष्य हों, इनकी प्राप्ति हेतु भारतीय अर्थव्यवस्था में महिला श्रम भागीदारी में वृद्धि एक अनिवार्य शर्त है।

श्रम शक्ति में महिलाओं की भागीदारी के आँकड़ों से शुरुआत की जा सकती है

श्रम बल भागीदारी के कारणों को संक्षेप में लिखें

महिला श्रम बल भागीदारी बढ़ने से लाभ

① समावेशिता के संदर्भ में
- वैश्विक लैंगिक अंतराल में भारत 135वें पर है। उसमें सुधार होगा।
- महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण होगा। वे सामाजिक सुरक्षा, बैंकिंग आदि से जुड़ेंगी।
- महिलाओं की सामाजिक स्थिति में भी सुधार होगा।

② सतत विकास लक्ष्यों के संदर्भ में

↳ अगले पृष्ठ पर।

Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

- श्रम बल भागीदारी बढ़ने से अर्थव्यवस्था के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि तेज होगी अतः SDG1, SDG2 आदि की दिशा में प्रगति तीव्र होगी।

स्पष्टीकरण ठीक है

- महिलाओं की आर्थिक भागीदारी उनको स्वयं के स्वास्थ्य पर निवेश करने में सक्षम बनाएगी। अतः सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद होगी।

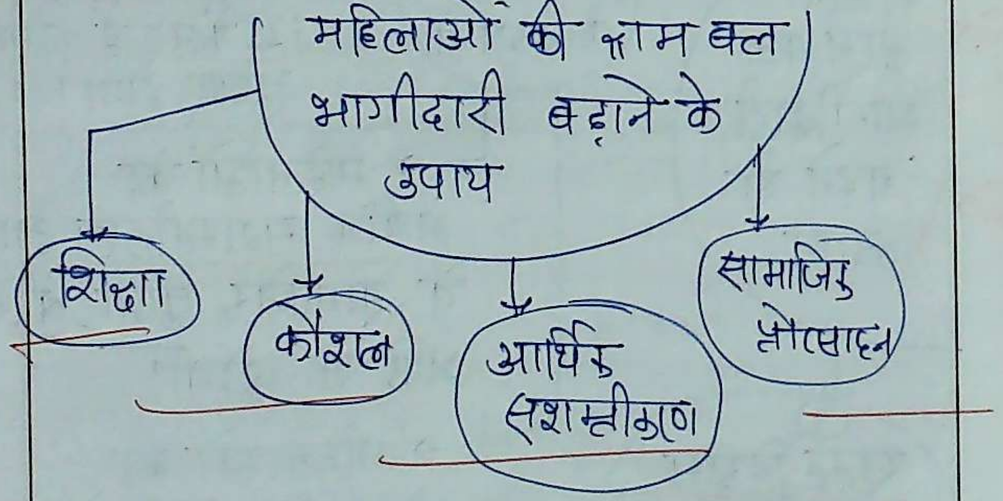

- महिलाओं का पुरुषों की तुलना में

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

भारत में सकल नामांकन अनुपात कम है। उच्च शिक्षा में इनकी भागीदारी कम है। इस दिशा में सुधार हेतु प्रावधान करने की जरूरत है।

→ आधारभूत ढाँचे तक महिलाओं की पहुँच बढ़ाना

- महिलाओं को दीन दयाल उपाध्याय आजीविका मिशन और स्किल इंडिया मिशन से जोड़ने की जरूरत है।
- स्वयं सहायता समूहों के बैंकों से सहयोग को तीव्र करने की जरूरत है।
- इस दिशा में स्टैंड अप इंडिया जैसी योजनाओं के संदर्भ में जागरूकता में वृद्धि की जरूरत है।
- महिलाओं एवं पुरुषों हेतु समान वेतन की अवधारणा को जमीनी स्तर पर लागू करने की जरूरत
- प्रसूति सहायता जैसे उपाय

वस्तुतः महिलाओं को STEM जैसे क्षेत्रकों में प्रवेश हेतु प्रेरित किए जाने की आवश्यकता है। → good.

7

अच्छा प्रयास है

Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

12. संसाधनों पर प्रतिस्पर्द्धात्मक लाभ और बड़ा घरेलू बाज़ार होने के बावजूद, भारत में खाद्य प्रसंस्करण पिछड़ा हुआ है। विश्लेषण कीजिये। (250 शब्द) 15

Despite having competitive advantage over resource endowments and large domestic market, food processing in India lags behind. Analyse. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

सरकार द्वारा खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रक की संभावनाओं का उपभोग करने हेतु इसे प्राथमिक क्षेत्रक ऋणदान (PSL), संपदा योजना आदि माध्यमों से मदद की जा रही है फिर भी यह क्षेत्रक अपेक्षित परिणाम नहीं दे पा रहा है।

खाद्य प्रसंस्करण की संकल्पना को संक्षेप में परिभाषित कर शुरुआत की जा सकती है

भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की संभावनाएँ
⇒ भारत एक बड़ी कृषि अर्थव्यवस्था है।
⇒ अधिशेष कृषि उत्पादन
⇒ कच्चे माल की उपलब्धता
⇒ विश्व का एक बड़ा एवं प्रमुख खाद्य प्रसंस्करण उपभोक्ता बाजार उपलब्ध है
⇒ दक्षिण एशिया एवं अन्यत्र निर्यात की संभावनाएँ मौजूद हैं।

drishti | दृष्टि The Vision

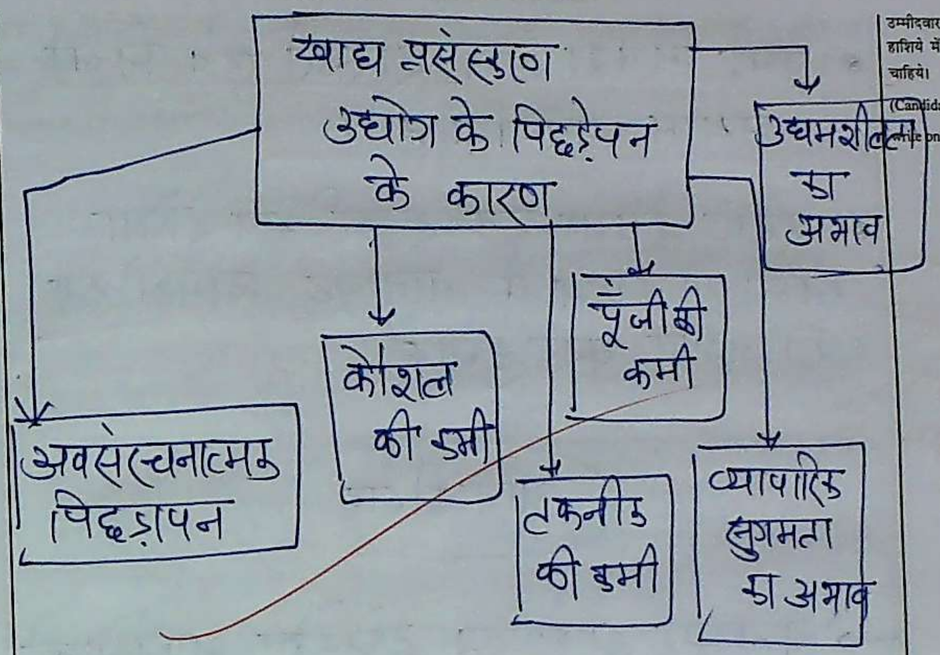

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

- वस्तुतः भारत में अभी भी कोल्ड स्टोरेज श्रृंखला आदि का पर्याप्त विकास नहीं हुआ है परिवहन अवसंरचना भी विश्व स्तरीय नहीं है।
- इस क्षेत्रक हेतु आवश्यक कुशल श्रमिक का भी अभाव है।
- खाद्य प्रसंस्करण हेतु उन्नत मशीनों एवं तकनीकों का अभाव भी एक सीमा है।

Copyright – Drishti The Vision Foundation

- पूंजी निवेश हेतु सरकारी एवं निजी प्रयास अवश्यक हैं।
- स्टैण्ड इंडिया एवं स्टार्ट अप इंडिया जैसी योजनाओं के बावजूद उद्यमशीलता का अभाव बना हुआ है।

इस दिशा में किए गए प्रयास को संक्षेप में लिखे

आगे की राह

→ क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत।

→ विकेंद्रित विकास की आवश्यकता। ग्रामीण क्षेत्रों में संयंत्रों की स्थापना।

→ फूडपार्क योजना, जैसी योजनाओं द्वारा समर्थन तीव्र करने की आवश्यकता।

प्रस्तुतीकरण के स्तर पर संतोषजनक कार्य किया गया है

6

वस्तुतः स्टार्ट अप इंडिया, सम्पदा योजना, कौशल भारत अभियान आदि के अभिसरण द्वारा इस क्षेत्र के विकास का प्रयास करने की जरूरत है। → ठीक है

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

13. हाल के वर्षों में भारत की गिग इकॉनमी में भारी उछाल आया है। हालाँकि, गिग इकॉनमी में महिलाओं के प्रवेश में संरचनात्मक बाधाएँ बनी हुई हैं। विश्लेषण कीजिये। (250 शब्द) 15
India's gig economy has witnessed an enormous surge in recent years. However, there remain structural barriers to women's entry into the gig economy. Analyse. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

पिछले कुछ वर्षों में इंटरनेट आधारित सेवा प्रदाता कंपनियों, जिनमें ऑनलाइन फूड डिलेवरी, आनलाइन टैक्सी, ऑनलाइन एजूकेशन, ई-मार्केटप्लेस आदि शामिल हैं, का तेजी से विकास हुआ है। इन्होंने गिग-कर्मियों की संख्या में तेजी से वृद्धि की है।

→ गिग इकॉनमी के संक्षिप्त परिभाषा से शुरुआत की जा सकती है

गिगकर्मी की अवधारणा

→ यह कंपनी में एक कर्मचारी के रूप में दर्ज नहीं होता है।

→ कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट आधारित संबंध होता है।

→ इन्हें सामान्य कर्मचारी जैसे वेतन, ग्रेच्युटी या अन्य सुविधाएं प्रायः नहीं मिलती हैं।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

गिग क्षेत्रक में महिलाओं के प्रवेश में संरचनात्मक बाधाएँ

1) क्षेत्रक विशिष्ट बाधाएँ

→ ड्राइविंग जैसे कौशल में महिलाएँ अत्यधिक पिछड़ी हुई हैं अतः उनके द्वारा फूड डिलीवरी जैसी या टैक्सी ड्राइवर जैसी सुविधाएँ देना मुश्किल।

→ ये कंपनियाँ प्रायः 24 घंटे सेवा प्रदान करती हैं। महिलाओं के लिए रात्रि में काम करने में सुरक्षा का दृष्टिकोण भी बाधा।

→ ऑनलाइन एजूकेशन जैसे क्षेत्रकों में महिलाओं की स्थिति अन्य की तुलना में ठीक है किंतु पर्याप्त नहीं

→ असमान वेतन

→ डिजिटल शिक्षा का अभाव

→ सामाजिक सुरक्षा जैसे - मैटरनिटी बेनिफिट्स, पेड लीव्स आदि का अभाव

→ इस क्षेत्र की सहयोग सम्बन्ध पहुँच में कमी

Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

2) सामान्य संरचनात्मक बाधाएँ

→ सामाजिक स्वीकार्यता की कमी।

→ परिवार में पितृसत्तात्मक ढाँचे में कार्यात्मक स्वतंत्रता का अभाव।

→ अभिप्रेरणा तत्व का अभाव।

इस दिशा में सरकार द्वारा महिलाओं को प्रोत्साहित करने वाली कंपनियों को कर छूट जैसी सुविधाएँ या अन्य सब्सिडी की व्यवस्था की जा सकती है।

इस पक्ष को विस्तार में लिखने से उत्तर का प्रवाह तथा चुनौतियाँ का समाधान से विश्लेषण स्पष्ट बन जायेगा।

6

Copyright – Drishti The Vision Foundation

14. "पीएम गति शक्ति योजना में दुनिया की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के साथ प्रतिस्पर्द्धा करने के लिये भारतीय बुनियादी ढाँचे और लॉजिस्टिक व्यवस्था को बदलने की क्षमता है।" समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिये। (250 शब्द) 15

"PM GATI SHAKTI has the potential to transform Indian infrastructure and logistics to compete with the world's leading economies". Critically analyze. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

PM- गति शक्ति योजना द्वारा अवसंरचना विकास के बहुआयामी दृष्टिकोण को अपनाया गया है इसके द्वारा 2040 तक भारतीय अर्थव्यवस्था के 40 ट्रिलियन तक पहुँचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की आशा की जा रही है

PM गति शक्ति
- स्थलीय
- नदी
- समुद्री

→ मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक प्रणाली का विकास

(1)

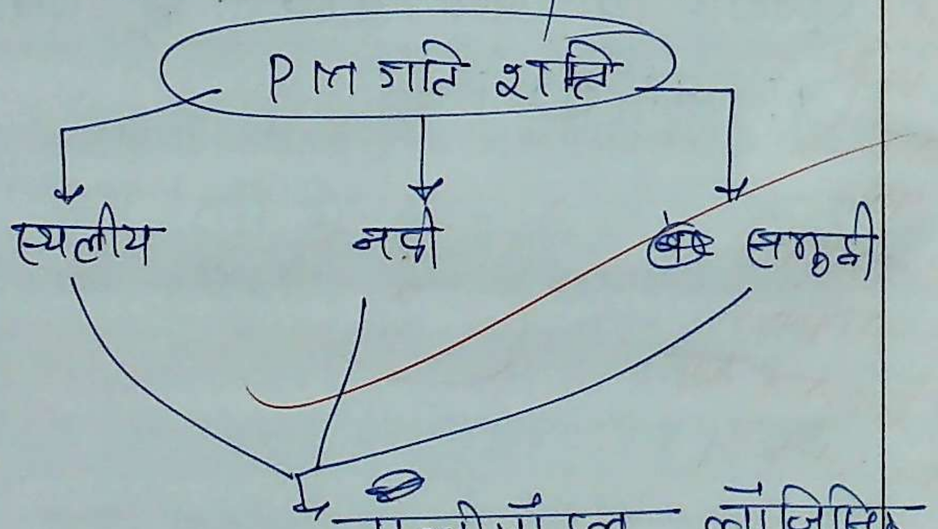

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

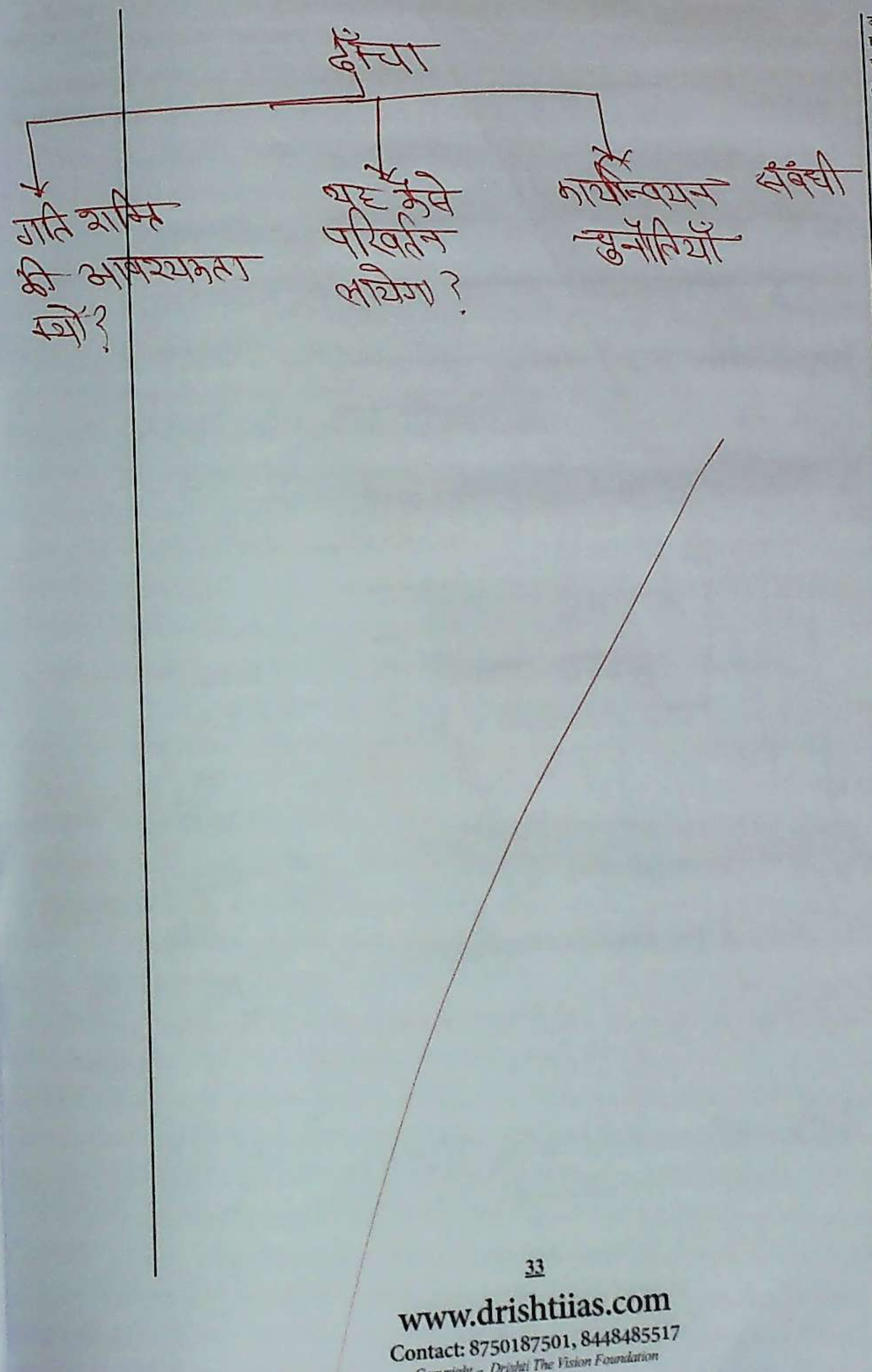

ढाँचा
- गति शक्ति की आवश्यकता क्यों?
- यह कैसे परिवर्तन लायेगा?
- कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियाँ

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

15. विभिन्न प्रकार के निवेश मॉडलों की चर्चा कीजिये। पी.पी.पी. (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) मॉडल से संबंधित मुद्दों पर प्रकाश डालिये। (250 शब्द) 15

Discuss the distinct types of investment models. Highlight the issues with the PPP (Public Private Partnership) model. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

सरकार द्वारा पीएम गति शक्ति, भारतमाला, इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन जैसी योजनाओं द्वारा लगातार निवेश हेतु निजी क्षेत्रक को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस दिशा में पी.पी.पी. मॉडल को सर्वाधिक उपयुक्त माना जा रहा है

निवेश को परिभाषित कर शुरुआत की जा सकती है

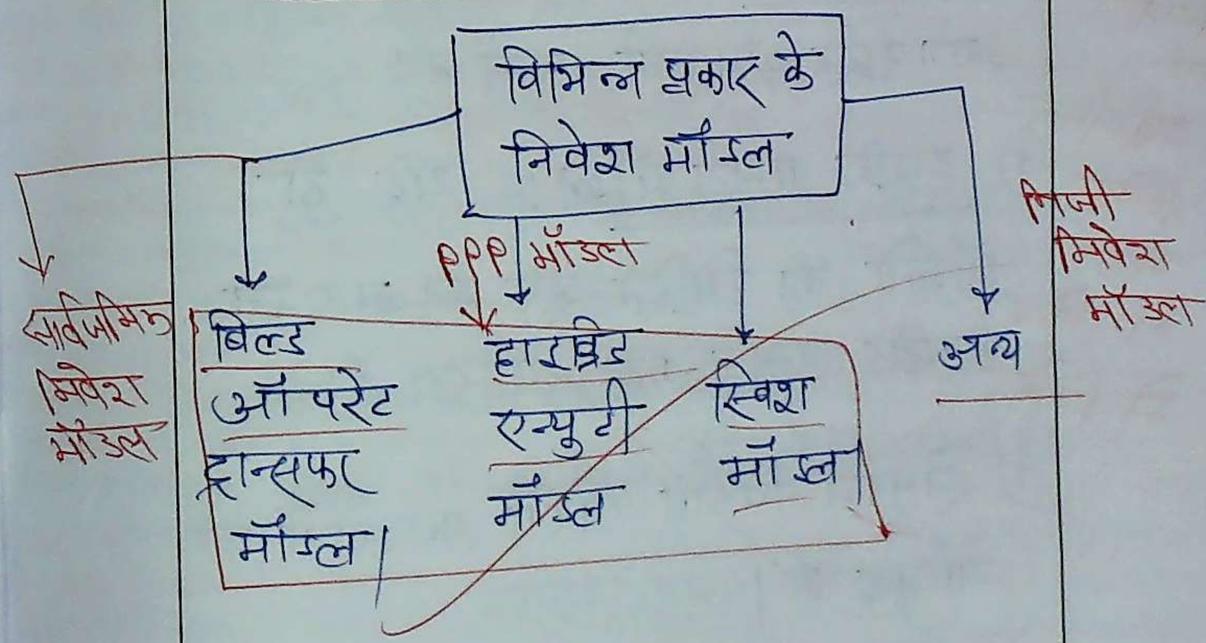

1) बिल्ड आपरेट ट्रान्सफर:- इस मॉडल

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

के अन्तर्गत निजी कंपनियाँ स्वयं की पूँजी से अवसंरचना निर्मित करती हैं एवं कुछ समय तक उसका संचालन कर लाभ एवं पूँजी की प्राप्ति करती हैं तत्पश्चात सरकार को स्वामित्व प्रदान कर देती हैं। उदाहरणार्थ :- हाइवे निर्माण।

2) स्विश मॉडल (चाइलेंज) :- इसके अन्तर्गत अलग पद्धति अपनायी जाती है।

3) हाइब्रिड एन्युटी मॉडल :- यह दो मॉडलों का मिश्रित रूप है अतः इसे हाइब्रिड एन्युटी कहा जा रहा है।

4) संयुक्त विकास जैसी प्रणालियाँ भी मौजूद हैं।

निजी एवं सार्वजनिक निवेश मॉडल को संक्षेप में लिखें

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

P.P.P. से संबंधित मुद्दे

=> COVID जैसी परिस्थितियों में आर्थिक मंदी के चलते निजी क्षेत्र की लागत में वृद्धि होती है, प्रतिफल भी प्रभावित होता है।

=> आर्थिक मंदी की स्थिति में निजी क्षेत्र पूँजी बाजार की कमजोरी का सामना कर रहा है।

=> परियोजनाओं के संबंध में विरोध, पर्यावरणीय लिटिगेशन जैसा रिस्क हमेशा बना रहता है अतः निजी क्षेत्र में उत्साह की कमी रहती है।

वस्तुतः PPP मॉडल में सभी पक्षों एवं संभावनाओं का व्यवहारिक मूल्यांकन किया जाना चाहिए।

→ जोखिम और जिसमें से बाधा के लिए तंत्र — अविश्वसनीय
→ खराब संस्थागत वातावरण
→ खराब प्रवर्तन तंत्र
→ कमजोर राजनीतिक और कानूनी ढाँचा
→ संसाधन न्यूनतम और गुणवत्ता के बीच असंतुलन
→ चुनौतियों के समाधान को प्रस्तुत करते हुए निष्कर्ष लिखा जा सकता है

(4)

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

16. बंदरगाह क्षेत्र को न केवल मज़बूत करने, बल्कि उसका विस्तार, विकास और आधुनिकीकरण करने की आवश्यकता है। टिप्पणी कीजिये। (250 शब्द) 15

There is a need not just to strengthen but expand, develop, and modernize our port sector. Comment. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

भारत का 70 प्रतिशत से अधिक व्यापार समुद्र मार्ग से होता है। साथ ही आंतरिक स्तर पर जलमार्गों के विकास की व्यापक संभावना है। इन सभी में बंदरगाहों की गुणवत्तापूर्ण अवसंरचना क्रांतिक महत्व रखती है।

→ ठीक है

बंदरगाह क्षेत्रक की मजबूती से लाभ

- परिवहन लागत में कमी आएगी। प्रतिस्पर्द्धात्मकता में वृद्धि होगी।
- बंदरगाहों पर लगने वाला समय कम होगा।
- ऊर्जा संरक्षण होगा।
- निर्यात में सुधार होगा।

प्रस्तुतीकरण अच्छी है

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयास

- सागरमाला परियोजना।
- बंदरगाहों के स्वामित्व में निजी क्षेत्रक को शामिल करने का प्रयास।
- नदी बंदरगाहों के विकास का प्रयास
- आधुनिकीकरण का प्रयास
- दक्षता पर बल

चुनौतियाँ को संक्षेप में लिख सकते हैं

क्या किए जाने की आवश्यकता है?

- बंदरगाहों का आकार एवं महत्व के अनुसार वर्गीकरण कर उनके स्वामित्व एवं प्रबंधन में निजीकरण में तेजी लायी जाय।
- भारत के पूर्वी तट पर बंदरगाह

→ बंदरगाह में तकनीक एवं आधुनिक मशीनों के प्रयोग को बढ़ावा देना।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

अवसंरचना पश्चिम की तुलना में कम विकसित है। इस दिशा में प्रयास की जरूरत है।

→पर्यावरणीय मंजूरी एवं भूमि अधिग्रहण में तीव्रता कर जमीन उपलब्ध कराना

⟹ बंदरगाहों की दक्षता समस्त व्यापार प्रणाली को प्रभावित करती है। बंदरगाहों की तकनीकी क्षमता में उन्नयन दक्षता में सुधार करेगा।

→हिंटरलैंड कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना

⟹ नदी मार्गों का विकास कर आंतरिक बंदरगाहों के विकास की जरूरत है।

→विजय केलकर समिति एवं नीति आयोग के अनुशंसाओं का क्रियान्वयन करना

वस्तुतः PM-गति शक्ति जैसी योजना इसमें क्रांतिकारी भूमिका निभा सकती है। →ठीक है।

6

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

17. भारत में विनिर्माण को प्रोत्साहित करने और विनिर्माण और सेवाओं में समर्पित निवेश के साथ अर्थव्यवस्था को उत्प्रेरित करने के लिये मेक इन इंडिया पहल अस्थिर-सी हो गई है। समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिये। (250 शब्द) 15

Make in India initiative to encourage manufacturing in India and galvanize the economy with dedicated investments in manufacturing and services is on a slippery slope. Critically analyze. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

भारतीय विनिर्माण नीति, 2011 के अनेक महत्वाकांक्षी लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में आगे चलकर मेक इन इंडिया अभियान की शुरुआत की गयी। इसका प्रमुख उद्देश्य भारत को विनिर्माण का वैश्विक हब बनाना था। →ठीक है →आत्मनिर्भर भारत

मेक इन इंडिया

- भारत में निर्माण हेतु निवेश आकर्षित करना
- व्यापार की सुगमता में सुधार करना
- रोजगार के अवसर सृजित करना
- निर्यात की वृद्धि एवं आयात के बोझ को कम करना
- तकनीकी हस्तांतरण

→विश्लेषण वाले प्रश्नों में पक्ष का प्रयोग करने से प्रभाविता और भी बढ़ती है

उदाहरण एवं तथ्यों के प्रयोग से विषयवस्तु को पुष्ट बनाया जा सकता है

उदा— विदेशी निवेशकों को 10 साल के लिए स्थायी निवासी का दर्जा

उदा— स्मार्ट सिटि, औद्योगिक गलियारे

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

मेक इन इंडिया की सफलता ⇒ खासतौर से इलेक्ट्रानिक विनिर्माण, रक्षा विनिर्माण आदि क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण सफलताएँ मिली हैं जैसे - एप्पल, सैमसंग आदि द्वारा निवेश।

→ इस योजना को PLI जैसी योजनाओं ने और सहायता प्रदान की है।

→ व्यापार सुगमता सूचकांक में भारत की स्थिति में लगातार सुधार हुआ है।

→ पनडुब्बी विकास, एयरक्राफ्ट आदि से संबंधित तकनीकों का हस्तांतरण भी संभव हुआ है। उदाहरणार्थ:- Project 75A

→ औद्योगिक गलियारा
→ स्मार्ट सिटी योजना
→ वोकल फॉर लोकल की बढ़ती लोकप्रियता
→ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

मेक इन इंडिया की सीमाएँ ⇒ (कोल्ड) चीन निवेश आकर्षित करने में उतनी सफलता नहीं मिली है।

→ रोजगार प्रदान करने में भी अपेक्षा के अनुरूप परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं।

→ आवश्यक कौशल, तकनीक के अभाव में कई कंपनियाँ निवेश करने से हिचकिचाती हैं।

→ श्रम कानून की जटिलता
→ भूमि अधिग्रहण की जटिलता
→ राज्यों के मध्य आम सहमति का अभाव
→ ऊर्जा की सीमित उपलब्धता

आगे की राह → कौशल भारत अभियान को तीव्र किया जाय।

→ COVID पश्चात परिवेश में चीन से निकल रही कंपनियों को आकर्षित किया जाय।

→ श्रम संहिता को जल्द से जल्द लागू किया जाय। → ठीक है

6

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

18. किसानों की आय दोगुनी करने के लिये कृषि में विकासात्मक पहल, प्रौद्योगिकी और नीतिगत सुधारों की आवश्यकता है। व्याख्या कीजिये। (250 शब्द) 15

Developmental initiatives, technology and policy reforms in agriculture are needed for doubling farmers' income. Elucidate. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

सरकार द्वारा 2022 को किसानों की आय दुगुनी करने के संदर्भ में कट ऑफ ईयर घोषित किया गया था। हालांकि COVID जैसी परिस्थितियों से उपजे अन्य कारकों से यह गति प्रभावित हुई है।

→ ठीक है

नीतिगत सुधारों का महत्व → सरकार द्वारा हाल ही में तीन कृषि कानूनों का निर्माण किया गया था किंतु यह प्रयास असफल रहा।

↳ कृषि क्षेत्रक में भारत में निजी निवेश अत्यंत कम है। इस हेतु कॉरपोरेट कृषि को प्रोत्साहित करने की जरूरत है।

↳ जी-एम- फसलों एवं अन्य नवाचारों

→ खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का

संदर्भ एवं प्रस्तुतीकरण अच्छी है

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

को स्वीकार करने के संदर्भ में सरकार की गति सुस्त रही है। इस दिशा में तीव्रतर प्रयास की जरूरत है।

⇒ भारतीय कृषि बाजार प्रणाली अत्यधिक विनियामकीय परिवेश में विकसित नहीं हो पा रही। इस दिशा में सुधार की जरूरत है।

⇒ कृषि निर्यात नीति, 2018 जैसी अन्य भविष्योन्मुखी नीतियों की आवश्यकता है।

कृषि क्षेत्र की चुनौतियों को संक्षेप में लिख सकते हैं

विकासात्मक पहल → फसल बीमा योजना का विस्तार सभी राज्यों में किए जाने की आवश्यकता है।

↳ कृषि क्षेत्रक में ऋण की औपचारिक उपलब्धता अब भी अपर्याप्त है जिसमें सुधार की जरूरत है।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

=> मृदा स्वास्थ्य कार्ड, PM-KISAN, किसान क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाओं की क्षमता में वृद्धि की आवश्यकता।

प्रौद्योगिकी सुधार → AI, ड्रोन, अंतरिक्ष, जैव प्रौद्योगिकी के कृषि अनुप्रयोग हेतु प्रयास की जरूरत।

→ भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल कृषि मशीनीकरण, कस्टम हायरिंग पद्धति आदि का विकास हो।

→ एक्सटेंशन सर्विसेज की गुणवत्ता में सुधार

→ R&D पर खर्च में वृद्धि

पशुधन नस्ल में सुधार

कृषि आँकड़ों से माँग के अनुसार फसल चयन

6.5

वस्तुतः बहुआयामी दृष्टिकोण द्वारा ही अपेक्षित लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है।

→ किसान के आय सुरक्षा के महत्त्व को उजागर करते हुए

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

19. भारत अकुशल अनाज प्रबंधन से ग्रस्त है जो खाद्य सुरक्षा को चुनौती देता है। चर्चा कीजिये। (250 शब्द) 15

India suffers from inefficient grain management which challenges food security. Discuss. (250 words) 15

प्रतिवर्ष भारतीय गोदामों में लाखों टन अनाज का नुकसान भारत में लगभग सामान्य क्रिया बन चुका है। इससे भारतीय खाद्य सुरक्षा के साथ-साथ वैश्विक खाद्य सुरक्षा भी प्रभावित होती है।

ग्लोबल हंगर इंडेक्स के आँकड़ों से शुरुआत की जा सकती है

अकुशल प्रबंधन से खाद्य सुरक्षा को चुनौती
→ अनाज की बर्बादी। FCI आदि द्वारा कुप्रबंधन।
=> आवश्यक वस्तु अधिनियम जैसी बाधाओं के चलते दक्ष प्रयोग सुनिश्चित करना मुश्किल अतः समय से खाद्य आपूर्ति प्रभावित होती है।
→ भंडारण की अवैज्ञानिक सीमाएँ

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

एवं प्रयास एक कुशल योजना निर्माण एवं क्रियान्वयन में बाधक बनते हैं।

→ हाल ही में यूक्रेन युद्ध के चलते उपजे वैश्विक खाद्य संकट में भारत द्वारा अभीष्ट योगदान न सुनिश्चित कर पाने के पीछे भी अकुशल प्रबंधन को दोषी माना जा रहा है।

→ सस्ते कीमत की दुकानों से लेकर FCI गोदामों एवं खरीद केंद्रों तक भ्रष्टाचार की व्याप्ति से खाद्य सुरक्षा प्रभावित होती है।

इस दिशा में अधोलिखित सुधार किए जाने की आवश्यकता है-

→ भंडारण क्षमता से अधिक अनाज क्रय

→ खुला बाजार परिचालन की भिन्न स्थिति

→ नियमों में एकरूपता का अभाव, विभिन्न राज्यों में

उदा— विभिन्न राज्यों में BPL के लिए अलग मानदंड है

Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

1) भंडारण क्षेत्रक में निजी क्षेत्रक को प्रोत्साहन
2) कृषि बाजार की प्रणाली का उदारीकरण।
3) कोल्ड स्टोरेज अवसंरचना में सुधार
4) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को प्रोत्साहन
5) अतिरिक्त अनाज का निर्यात
6) भ्रष्टाचार पर नियंत्रण

वस्तुतः इस दिशा में प्रयास की शुरुआत खाद्य सुरक्षा अधिनियम, FCI अधिनियम, आवश्यक वस्तु अधिनियम आदि में संरचनात्मक परिवर्तन द्वारा होनी चाहिए

→ अंत्योदय परिवार को छोड़ अन्य को खरीद का 50% पर बेचना

→ 70 मार्क के जगह 40% लोगों को ही खाद्य सुरक्षा

→ MSP नीति में सुधार कर दालों, तिलहन पर

→ FP में POS मशीन को अनिवार्य करना।

→ सीएसई रिपोर्ट द्वारा दिए गए आँकड़ों (लगभग 40% अनाज उपभोक्ता तक पहुँचने से पहले नष्ट जिससे वार्षिक तौर पर 50 हजार करोड़ रुपए का नुकसान

5.5

Copyright – Drishti The Vision Foundation

20. अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि असंगठित क्षेत्र को संगठित क्षेत्र में परिवर्तित करने के लिये संरचनात्मक परिवर्तन की आवश्यकता होगी। इस संबंध में औपचारीकरण के विभिन्न लाभों और चुनौतियों पर चर्चा कीजिये। (250 शब्द) 15

It has often been argued that it will take a structural transformation for the unorganized sector to become organized. In this regard discuss the numerous benefits and challenges to formalization. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

भारत के आर्थिक पिछड़ेपन में अक्सर इसके अनौपचारिक क्षेत्र की अधिव्याप्ति को जिम्मेदार माना जाता है। आज भी भारत का अधिकांश श्रम बल असंगठित क्षेत्र का हिस्सा है।

संगठित एवं असंगठित क्षेत्र के संक्षिप्त परिचय से शुरुआत की जा सकती है।

संदर्भ दक्षता एवं प्रकृतीकरण [illegible]

औपचारीकरण के लाभ:

- सरकार तक वास्तविक एवं विश्वसनीय आँकड़े होंगे। नीति निर्माण कुशल एवं प्रभावी होगा।
- अर्थव्यवस्था की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार होगा।
- कार्यरत कर्मचारियों को सभी प्रकार के लाभ एवं सामाजिक सुरक्षा की प्राप्ति होगी।
- विभिन्न कार्य क्षेत्रों की निगरानी में मदद होगी।
- रोजगार की सुरक्षा
- सुरक्षित वातावरण का आश्वासन
- काम के घंटे निश्चित

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

औपचारीकरण में आने वाली चुनौतियाँ:

- पूँजी का अभाव है जिससे उद्योगों का विस्तार प्रभावित होता है।
- तकनीक एवं कौशल का अभाव
- अवसंरचनात्मक बाधाएँ भी मौजूद हैं।
- आर्थिक सर्वेक्षण 2020 में कहा गया कि सब्सिडी जैसी नीतियाँ अविवेकी होने के चलते उद्योगों को छोटा बने रहने को प्रोत्साहित करती हैं अप्रत्यक्ष रूप से।
- पर्याप्त उद्यमशीलता की कमी।
- अनौपचारिक क्षेत्र में बड़ी संख्या में छोटे उत्पादक
- प्रशासन संबंधी खामियाँ
- श्रमिकों के मध्य शिक्षा, जागरूकता अभाव

इस दिशा में अधोलिखित परिवर्तन किए जाने की जरूरत है।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

1) इकॉनॉमी आफ स्केल की अवधारणा पर सरकारी सहायता प्रदान की जाय।

2) सरकार द्वारा स्वयं पेटेंट आदि खरीदकर उद्योगों को उपलब्ध कराया जाय।

3) विशेषीकरण को प्रोत्साहन दिया जाय।

4) ऋण उपलब्धता में वृद्धि की जाय।

5) G.S.T. जैसी प्रणाली में MSME को दृष्टिगत रखकर बदलाव किया जाय।

स्किल इंडिया एवं मेक इन इंडिया को सफल बनाना

→ श्रम कानून संहिता, 2020 का क्रियान्वयन करना

→ बैंकिंग सेक्टर की सेहत को मजबूत बनाना

6.5

अच्छा प्रयास है

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

Space for Rough Work
(रफ कार्य के लिये स्थान)

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation